



ग्रीन बॉण्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रज़िर्व बैंक](#) (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में सूचना वषिमता (Asymmetric Information) के कारण ग्रीन बॉण्ड जारी करने की लागत प्रायः अन्य बॉण्डों की तुलना में अधिक रही है।

प्रमुख बिंदु:

ग्रीन बॉण्ड (विवरण):

■ ग्रीन बॉण्ड के बारे में:

- ग्रीन बॉण्ड ऋण प्राप्तिका एक साधन है जिसके माध्यम से ग्रीन 'परियोजनाओं के लिये धन जुटाया जाता है, यह मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है।
 - बॉण्ड जो कर्जा का एक नश्चिति साधन होता है, एक नविशक द्वारा उधारकर्त्ता (आमतौर पर कॉर्पोरेट या सरकारी) को दिये गए ऋण का प्रतनिधित्व करता है।
 - पारंपरिक बॉण्ड (ग्रीन बॉण्ड के अलावा अन्य बॉण्ड) द्वारा नविशकों को एक नश्चिति ब्याज दर (कूपन) का भुगतान किया जाता है।

■ वृद्धि:

- वर्ष 2007 में यूरोपीय नविश बैंक और [वशिव बैंक](#) जैसे कुछ बैंकों द्वारा ग्रीन बॉण्ड लॉन्च किया गया। इसके बाद वर्ष 2013 में कॉर्पोरेट्स द्वारा भी इन्हें जारी किया गया जिस कारण इसका समग्र विकास हुआ।

■ वनियमन:

- [भारतीय प्रतभित और वनियमि बोरड](#) (Securities and Exchange Board of India- SEBI) द्वारा ग्रीन बॉण्ड जारी करने एवं इन्हें सूचीबद्ध करने हेतु पारदर्शी मानदंडों को लागू किया गया है।

■ लाभ:

○ प्रतषिठा में बढ़ोतरी:

- ग्रीन बॉण्ड जारीकर्त्ता की प्रतषिठा को बढ़ाते हैं, क्योंकि यह [सतत् विकास](#) के प्रतउनकी प्रतबिद्धता को प्रदर्शित करने में सहायक है।

○ प्रतबिद्धताओं की प्रतः

- इनमें जलवायु समझौतों और इन पर हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा अन्य हरति प्रतबिद्धताओं को पूरा करने की क्षमता है।
- भारत का [राष्ट्रीय सतर पर नरिधारति योगदान](#) (Intended Nationally Determined Contribution- INDC) दस्तावेज़ जलवायु सुधार की दशा में भारत के योगदान और प्रगतिके लिये एक कम कार्बन पथ का अनुसरण करने के लक्ष्य का उल्लेख करता है।

○ कम लागत को बढ़ावा:

- आमतौर पर वाणजियकि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की तुलना में ग्रीन बॉण्ड पर कम ब्याज लिया जाता है।
- हरति नविश वदिशी नविशकों को आकर्षित करने के साथ-साथ पूंजी जुटाने की लागत को कम करने में मदद कर सकता है।

○ सनराइज़ सेक्टर

- ग्रीन बॉण्ड अक्षय ऊर्जा जैसे सनराइज़ सेक्टर के वतितपोषण को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण रहे हैं, इस प्रकार यह भारत के सतत् विकास में योगदान देते हैं।

RBI द्वारा किये गए हालिया अध्ययन का विवरण:

■ वर्तमान शेर:

- वर्ष 2018 के बाद से भारत में जारी सभी प्रकार के बॉण्ड में ग्रीन बॉण्ड का हसिसा मात्र 0.7% रहा है।
- हालाँकि मार्च 2020 तक गैर-पारंपरिक ऊर्जा के लिये बैंकों द्वारा दिये जाने वाला ऋण, वदियुत क्षेत्र के बकाया कुल बैंक ऋण का लगभग 7.9 प्रतशित है।
 - भारत में ज्यादातर ग्रीन बॉण्ड सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों या कॉर्पोरेट्स द्वारा बेहतर वतितीय स्थतिको ध्यान में रखकर

जारी किये जाते हैं।

■ चुनौतियाँ :

○ उच्च कूपन दर:

- 5 से 10 वर्षों के मध्य की परपिकव अवधि के साथ वर्ष 2015 के बाद से जारी किये गए ग्रीन बॉण्ड के लिये औसत कूपन दर सामान्यतः इसी अवधि की कॉर्पोरेट सरकार (Corporate Government) के बॉण्ड की तुलना में अधिक होती है।

○ उधार लेने की उच्च लागत:

- सूचना वषिमता के कारण यह सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौती रही है। उच्च कूपन दर अधिक उधार लेने की लागत के कारणों में से एक है।
- सूचना वषिमता, जिसे "सूचना वफिलता" के रूप में भी जाना जाता है, की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आर्थिक लेन-देन के लिये एक पक्ष के पास दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक भौतिक ज्ञान होता है।

■ सुझाव:

- भारत में एक बेहतर सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करने से परपिकवता असमानता को कम करने, उधार लेने की उच्च लागत और विभिन्न चरणों में उधार लेने की लागत और संसाधनों के कुशल आवंटन में मदद मिल सकती है।

अन्य चुनौतियाँ:

धन का दुरुपयोग:

- यह गंभीर चर्चा का विषय है कि क्या ग्रीन बॉण्ड जारी करने वालों द्वारा लक्षित परियोजनाएँ पर्याप्त रूप से हरित परियोजनाएँ ही हैं क्योंकि ग्रीन बॉण्ड से प्राप्त आय का उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु किया जा रहा है।

क्रेडिट रेटिंग का अभाव:

- हरित परियोजनाओं और बॉण्डों के लिये क्रेडिट रेटिंग या रेटिंग दशा-नरिदेशों का अभाव है।

अल्पावधि:

- भारत में ग्रीन बॉण्ड की अवधि लगभग 10 वर्ष होती है, जबकि एक सामान्य ऋण की न्यूनतम अवधि 13 वर्ष होती है। इसके अलावा ग्रीन प्रोजेक्ट्स का लाभ मिलने में भी अधिक समय लगता है।

आगे की राह:

- सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक ग्रीन बॉण्ड बाजार को विकसित करने के लिये अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दशा-नरिदेशों एवं मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। हरित निवेश के संदर्भ में भी समरूपता की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न कर-सीमाएँ एक नरिधारित सीमा से परे ग्रीन बॉण्ड बाजार के लिये वरिधाभासी होंगी।
- उभरते बाजारों में जारीकर्त्ताओं के लिये उचित क्षमता नरिमाण का प्रयास, जो ग्रीन बॉण्ड से संबंधित लाभों और प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान करते हों, इस बाजार में प्रवेश करने हेतु संस्थागत बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा।
- रणनीतिक रूप से ग्रीन बॉण्ड के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश नरिजी निवेश को आकर्षित करने और साथ ही ग्रीन बॉण्ड बाजार में निवेशकों का विश्वास स्थापित करने में मदद करता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस